संपादकीय

शांति और संवाद की जरूरत

जिस देश में गाँधी को राष्ट्र-पिता का दर्जा दिया गया है वह देश आज उनके सिद्धांतों से बहुत दूर निकल गया है। आज हमारी सड़कें और सोशल मीडिया बदले की मांगों से भरा पड़ा है। पुलवामा के आतंकी हमले के बाद कश्मीरी विद्यार्थी और मुस्लिम बिरादरी एक असुरक्षा का भाव महसूस कर रहे हैं और सरकारें प्रतिहिंसा की तैयारी में लगी हैं। हम लोग ऐसे समूहों के हिस्से भी हैं और गवाह भी, जहाँ हमसे भिन्न सभी लोगों के लिए नफरत और दुश्मनी की भाषा का प्रयोग हो रहा है। ये कथित गौ-व्यापार में शामिल लोगों के लिए हो या सड़कों पर कबाड़ बीन रहे लोगों के लिए, या उनका अपराध सिर्फ हमसे भिन्न वंश और मूल के होने का हो। ऐसे में बीच-बीच में इंसानियत के लिए उठ रहीं कुछ संतुलित ध्वनियां देशद्रोह के नाम पर दबाई जा रही हैं।

हम लोग अपने आपको इंसान के रूप में पहचानने में असफल हुए हैं। जाति, रंग, धर्म, क्षेत्र की दीवारों ने हमें अंधा कर दिया है आप किस तरफ हो, इसे चुनने के आधारों में कोई परिपक्वता दिखाई नहीं देती। क्या हम मानवता के पाले में खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा सकते ? सोशल मीडिया पर आ रहे विभिन्न संदेशों में एक सन्देश बहुत सटीक है- %आप एक शहीद कहलाओगे, अगर आप जंग में दूसरे की गोली से मारे गए, एक पीड़ित कहलाओंगे, अगर आप निहत्थे मारे गए, एक बहादुर देशप्रेमी सैनिक या एक आतंकवादी कहलाये जा सकते हो, अगर आपने दूसरे पक्षवाले को मारा या फिर एक देशद्रोही कहलाओंगे, यदि आपने शांति की बात की।%

आज फिर मीडिया की सुर्खियां एक और समूह की मौत की खबरों से भरी हुई हैं। ये सीआरपीएफ (केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल) के जवान देश के विभिन्न हिस्सों से अपने परिवारों से मिलकर वापस ड्यूटी पर आ रहे थे। इस बार हिंसा के मार्ग पर चलने वाले एक और व्यक्ति ने आक्रमण किया था। सवाल है, एक 21 वर्षीय पढ़ा-लिखा भारतीय नागरिक आदिल डार क्यों इस रास्ते पर चला गया ? इस प्रक्रिया में वो क्यों अपनी जान देना चाहता था ? क्यों उसके जीने की वह इच्छा, जो हरेक जीवित प्राणी में प्राकृतिक रूप से मौजूद रहती है, देश की रक्षा करने वालों को मार डालने के ऊपर हावी नहीं हुई? क्यों उसने उम्मीद खो दी ? किसी भी सामाजिक समूह या संगठन के हथियार उठाने को वाजिब न मानते हुए, हम लोग समझ सकते हैं कि क्यों कुछ समूह राज्य के साथ एक सशस्त्र युद्ध का विकल्प चुन लेते हैं। हमें ईमानदारी से स्वीकारना होगा कि मुख्यधारा के भारत ने देश के कुछ क्षेत्रों के लोगों और नागरिकों के स्वतंत्रता, सम्मान, जीवन, स्व-शासन के अधिकारों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है हमने भी अपने शहरी इलाकों से इन खून-खराबे के क्षेत्रों में रहने वाली आबादी की तरफ नजर नहीं डाली है, चाहे वो देश का कोई भी इलाका हो।

हिंसा और युद्ध की समीक्षा करते हुए हमें सत्ता के हाथों इस्तेमाल की जा रही हिंसा पर भी नजर डालनी चाहिए। मुख्यधारा में यह इतनी आसानी से वाजिब ठहराई जाती है कि मानव अधिकारों की बात करने वालों के अलावा %हिंसा% को राज्य से जोड़कर कोई नहीं देखता। हालांकि वोट से बनी सरकारों द्वारा सत्ता के सर्वव्यापी दुरुपयोग के उदाहरणों को अनदेखा नहीं किया जा सकता, चाहे वो जर्मनी की नाजी सरकार द्वारा लाखों यहूदियों और रोमा जिप्सीज को मारे जाने के काले साल हों, या गुजरात सरकार की 2002 के दंगों में भूमिका की बात हो या इंदिरा गाँधी की हत्या के पश्चात् भड़की हिंसा में सत्तारूढ़ कांग्रेस की भूमिका। पिछले साल मई में तूतीकोरिन (तमिलनाडु) में पुलिस द्वारा औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ संघर्षरत 12 लोगों के मारे जाने की वारदात राजकीय ताकतों के दुरूपयोग का क्रूर उदाहरण है हाल में अबूझमाड (बीजापुर, बस्तर) में दस लोगों का मारा जाना नई सरकार की एक और उपलब्धि की तरह पेश किया जा रहा है।

आतंक से निपटने की अरबी तजबीज

यूरोप के देशों व तुर्की व भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों की तुलना में अमीरात को अब भी एक लंबा सफर तय करना है। लोकतांत्रिक अधिकारों के मामले में इसे अपना रिकार्ड काफी सुधारना है। मगर महत्वपूर्ण यह है कि इसके हुक्मरानों ने सहिष्णुता व अमन के महत्व को पहचान लिया है, जबकि भारत व तुर्की के हुक्मरान उदारवाद की शानदार संवैधानिक विरासत के बावजूद उलटी यात्रा पर हैं, जिसे देश के पढ़े-लिखे मध्यवर्ग के एक बड़े हिस्से का समर्थन भी है। यूएई का सफर अभी लंबा है, मगर उसने सही राह पकड़ ली है।

यह स्वाभाविक था कि पुलवामा में आतंकी हमले के कुछ दिन बाद ही सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान और भारत यात्रा पर देशवासियों की नजर टिक जाए। यूं सऊदी अरब आतंकवाद व कट्टरता के पोषकों में शुमार किया जाता है। सलमान ने पाकिस्तान में साझे बयान में कहा कि आंतकियों की संयुक्त राष्ट्र की सूची का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। यह एक तरह से मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की भारत की मांग का जवाब था। बाद में भारत के साथ साझा बयान में आतंकवाद शब्द तो आया मगर न तो पाकिस्तान का नाम लिया गया और न पुलवामा का जिक्र आया। सऊदी प्रतिनिधिमंडल में शामिल उद्योगपतियों की मुकेश अंबानी की रिलायंस के साथ निवेश की बात आगे बढ़ाने समेत दूसरे निवेशों के हासिल को छोड़ दें तो प्रिंस की यात्रा ने देश को निराश ही किया। शायद भारत का ध्यान भी अभी व्यापारिक संभावनाओं पर ही ज्यादा हो।

सऊदी क्राउन प्रिंस की पाक-परस्ती को खाड़ी देशों में आतंकवाद और सहिष्णुता को लेकर खड़ी जबरदस्त बहस के मद्देनजर देखा जाना चाहिए। आतंकवाद की आंच आखिरकार खाड़ी के देशों तक भी पहुंच गई है। बयानबाजियों के बावजूद सऊदी अरब के पैर अब भी कट्टरता की दलदल से बाहर नहीं निकले हैं, वहीं इसी का पड़ोसी मुल्क संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) अमन व सहिष्णुता की उम्मीद बन कर सामने आया है। वैसे यूएई दुबई और अबुधाबी जैसे चमचमाते, साफ-सुथरे और संपन्न शहरों, व्यापार और सैर-सपाटे के लिए जाना जाता है, मगर हमें पता होना चाहिए कि हाल में इस देश ने एक नया इतिहास रचते हुए सहिष्णुता और सद्भाव के परचम को ऊँचा लहरा दिया। इस कदम का असर अपेक्षाकृत अनुदार माने जाने वाले खाड़ी देशों पर कितना पड़ेगा, यह देखना होगा, लेकिन इसने आतंकवाद व कट्टरता से जूझती दुनिया के लिए एक उम्मीद पैदा की है। यह घटनाक्रम भारत व तुर्की जैसे उन मुल्कों के लिए भी महत्व रखता है, जहां धर्मनिरपेक्षता की बाकायदा संवैधानिक हैसियत और परंपरा होते हुए भी पिछले कुछ सालों से असहिष्णु और उन्मादी विचारधाराओं ने सिर उठा लिया है।

दो साल पहले यूएई के हुक्मरान शेख मोहम्मद शेख बिन जायद अलनाह्यान कैथोलिक ईसाइयों के धर्मगुरु पोप फ्रांसिस को आमंत्रित करने वेटिकन गए थे। नतीजे में इसी साल फरवरी के पहले हफ्ते अमीरात पहुंचे पोप का जबरदस्त स्वागत किया गया। पोप की यह यात्रा इस मायने में ऐतिहासिक है कि वे इस्लाम के 1400 साल के इतिहास में अरब प्रायद्वीप की जमीन पर कदम रखने वाले पहले पोप बन गए हैं। वह भी इतिहास के उस दौर में, जब सभी धर्मों के बीच कट्टरपंथी सर उठा रहे हैं, जब सभ्यताओं के आपसी संवाद की जगह सभ्यताओं के संघर्ष की बात की जा रही है और खास-तौर पर तब,जब इस्लाम व ईसाइयत के बीच झगड़े की छवियां हावी हो गई हैं। जब सभी धर्मों के कट्टरपंथी टेक्नोलॉजी की जोड़-तोड़ के जरिए दूसरे धर्मों की रूढ़ छवियां गढ़ने पर आमादा हों, जब एक धर्म का उन्माद दूसरे धर्म के उन्माद से वैधता पाने की कोशिश कर रहा हो और जब तमाम धर्मों के उदार व सहिष्णु हिस्से नक्कारखाने में तूती बजाने पर मजबूर होते जा रहे हों तब धर्मगुरु की यह यात्रा बेहद सामयिक और असरकारी हो जाती है।

यूएई में पोप की यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक थी। पोप की अगुवाई में अबूधाबी के एक स्टेडियम में करीब 35 हजार ईसाइयों का खुला धर्म-समागम या मास आयोजित हुआ। स्टेडियम के बाहर से करीब एक लाख लोग इसमें हिस्सा ले रहे थे। मगर इससे ज्यादा अहम था, एक सर्वधर्म सभा का आयोजन, जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख धर्मगुरुओं ने हिस्सा लिया। दो दिन के इस इंसानी भाइचारे पर सम्मेलन' में 600 धर्मगुरु शामिल थे। इस सभा में पोप के अलावा आकर्षण का बड़ा केंद्र थे, सुन्नियों की शीर्ष धार्मिक हस्तियों में से एक शेख अहमद अल-तैयब, जो काहिरा की काफी पुरानी व प्रतिष्ठित अल-अजहर यूनिवर्सिटी के इमाम हैं। इमाम तैयब कट्टरपंथ से प्रभावित जिहादियों के कड़े आलोचक के रूप में मशहूर हैं।

इस सम्मेलन में महसूस किया गया कि दुनिया का कोई भी धर्म कट्टरपंथियों के असर से मुक्त नहीं है। इसलिए एक-दूसरे की तरफ उंगलियां उठाकर नफरत को और बढ़ाने की जगह सभी धर्मों के बुनियादी मूल्यों के सामने खड़ी हो रही नई चुनौतियों की साझी समझ बनाने की जरूरत है। ताकि धर्म दमन, हिंसा या युद्ध की ताकतों के हाथ का औजार न बन कर रह जाए और किसी संकीर्ण राजनीतिक विचारधारा में तब्दील न हो जाए। इस सम्मेलन का बड़ा हासिल यह है कि इसने धर्मों की नकाब ओढ़कर काम करने वाली उग्रवादी व उन्मादी राजनीतिक विचारधाराओं को खुली चुनौती दी है। एक तरह से यह घोषणापत्र तमाम धर्मों के मानवीय व उदारवादी हिस्सों से एकजुटता की अपील करता है। पोप और इमाम अरबी परंपरा के मुताबिक एक-दूसरे के गालों को चूमते हुए गले मिले। दोनों ने अबूधाबी में आजू-बाजू बनाए जाने वाले गिरिजाघर और मस्जिद की बुनियाद रखी। सरकार ने यह एलान किया कि मशहूर बिन-जायद मस्जिद को अब ईसा की मां मैरी के नाम से %मैरी मस्जिद% के रूप में जाना जाएगा। गिरिजाघर व मस्जिद का पड़ोस और ईसा की मां के नाम पर एक मस्जिद का नामकरण सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है। यह दोनों धर्मों के सहिष्णु व उदार तबकों का एक-दूसरे का हाथ पकड़कर धर्म के मर्म के करीब जाना है।

पोप व तैयब ने विश्व शांति व साझे जीवन के लिए इंसानी भाई-चारे के एक साझे घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए। इस घोषणापत्र में हिंसा व आतंकवाद को ठुकराने, महिलाओं व बच्चों के अधिकारों की पुष्टि करने और विकास व न्याय की हिमायत करने की बात की गई है। घोषणापत्र पर हस्ताक्षर के ठीक पहले इमाम तैयब ने एक वक्तव्य देकर तमाम देशों से अलग-अलग धर्मों के अनुयायियों को समान नागरिक अधिकार देने की अपील की।

इस मौके पर अमीरात सरकार ने एलान किया कि एक उदार और समावेशी मुल्क बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए 2019 को सहिष्णुता वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इसी के साथ एक सहिष्णुता मंत्रालय' के गठन और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता संस्थान की स्थापना की घोषणा भी की गई है। हर साल राष्ट्रीय सहिष्णुता, सद्भावना व सह-अस्तित्व उत्सव मनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत 2018 में ही नवंबर माह से हो गई है।

संयुक्त अरब अमीरात की सहिष्णुता की तरफ यह छलांग अनायास नहीं है। यहां बदलाव की शुरुआत कुछ पहले से हो गई थी। वर्ष 1960 में अमीरात में पहला चर्च बन गया था। सऊदी अरब की तरह अमीरात भी कट्टर वहाबी असर वाला देश है। मगर यह सऊदी अरब की तरह इस्लामी आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता। अब यह अरब देशों में खुलेपन व सद्भाव की उम्मीद की किरण बन रहा है। वहीं सऊदी अरब अमेरिकी साम्राज्यवाद की सरपरस्ती में कट्टरता के निर्यात का ऐसा केंद्र बना है जहां सामंतवाद व पितृसत्ता की संरचनाओं को बचाने के लिए धर्म को औजार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। सऊदी अरब के अमेरिकी भू-राजनीति का कहर बनने का असर यह भी हुआ है कि मध्यपूर्व कट्टरता व उन्माद के दलदल में फंसता गया है। हालांकि मुस्लिम ब्रदरहुड व आईएसआईएस जैसे भस्मासुर पैदा होने के बाद से सऊदी अरब के एक हिस्से में काफी बैचेनी है। सऊदी अरब को छोड़कर बाकी अरब देशों में दूसरे धर्मावलंबियों को अपने पूजा स्थल बनाने की इजाजत है। यूएई में चालीस चर्च व कई मंदिर हैं। एक काफी बड़ा हिंदू मंदिर निर्माणाधीन है। यहां डेढ़ सौ से ज्यादा देशों के लोग नौकरी करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा दक्षिण एशिया से हैं। यहां जनसंख्या का नौ फीसदी ईसाई, सात फीसदी हिंदू व दो फीसदी बौद्ध हैं।

हालांकि यूरोप के देशों व तुर्की व भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों की तुलना में अमीरात को अब भी एक लंबा सफर तय करना है। लोकतांत्रिक अधिकारों के मामले में इसे अपना रिकार्ड काफी सुधारना है। मगर महत्वपूर्ण यह है कि इसके हुक्मरानों ने सहिष्णुता व अमन के महत्व को पहचान लिया है, जबकि भारत व तुर्की के हुक्मरान उदारवाद की शानदार संवैधानिक विरासत के बावजूद उलटी यात्रा पर हैं, जिसे देश के पढ़े-लिखे मध्यवर्ग के एक बड़े हिस्से का समर्थन भी है। यूएई का सफर अभी लंबा है, मगर उसने सही राह पकड़ ली है।

कर्फ्यू और धारा 144 में अंतर

आपको बता दें कि कर्फ्यू का आदेश एक विशिष्ट समूह के लिए या फिर आम जनता के लिए हो सकता है। यह पुलिस की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी बाहरी गतिविधि को प्रतिबंधित करता है।

लोगों का एक समूह सार्वजनिक शांति भंग करने के इरादे से इकट्ठा होता है, तो ऐसे समूह को गैर-कानूनी समूह के रूप में जाना जाता है। ऐसी प्रक्रियाओं को रोकने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानि सीआरपीसी की धारा 144 और कर्फ्यू जैसे प्रावधानों का उपयोग किया जाता है।

किसी भी क्षेत्र या शहर में दंगा, लूटपाट, आगजनी या शहर के हालात बिगड़ने के कारण धारा 144 लगाई जाती है। यह जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी किया गया एक नोटिफिकेशन होता है। इसके लागू होने पर किसी स्थान पर 5 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। उस स्थान पर हथियारों के लाने और ले जाने पर भी रोक होती है। इसका उल्लंघन करने पर गिरफ्तार भी किया जा सकता है। धारा 144 लागू होने के बाद पुलिस जब किसी भी प्रकार की गैरकानूनी समूह को रोकती है तो वह भी दंडनीय अपराध माना जाता है। ऐसे लोगों को दंगों को बढ़ावा देने के लिए भी बुक किया जा सकता है। धारा 144 अधिकारियों को इंटरनेट का उपयोग करने पर रोक लगाने का भी अधिकार देती है।

दूसरी ओर कर्फ्यू के आदेश, किसी भी स्थान या शहर के हालात ज्यादा बिगड़ने पर दिए जाते हैं। इसमें लोगों को एक विशेष समय या अवधि के लिए घर में ही रहना होता है। ऐसा माना जाता है कि यह किसी भी प्रकार की हिंसक स्थिति को संभालने में काफी मददगार साबित हो सकता है। आपको बता दें कि कर्फ्यू का आदेश एक विशिष्ट समूह के लिए या फिर आम जनता के लिए हो सकता है। यह पुलिस की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी बाहरी गतिविधि को प्रतिबंधित करता है। केवल आवश्यक सेवाओं की अनुमति होती है, जैसे रोजमर्रा की जरूरतों के लिए कुछ समय तक बाजार का खुलना लेकिन स्कूलों को बंद रहने का आदेश दिया जाता है। कर्फ्यू लगाने से पहले धारा 144 लगाई जाती है और एक तय समय सीमा में आपको अपने घर पहुंचना होता है।

युद्धोन्माद की बजाए शांति और मैत्री को मौका दें

मोदी ने एक भी ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मौका नहीं छोड़ा होगा जहां उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद को संरक्षण देने के लिए अलग-थलग करवाने की कोशिश न की हो, किंतु वे किसी एक भी महत्वपूर्ण देश को अपनी बात मनवा नहीं पाए। जैश-ए-मोहम्मद का मसूद अजहर, जिसका 2001 के संसद भवन पर हमले से लेकर हाल के पुलवामा हमले तक में हाथ है, को संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करवाने के प्रयास में चीन ने हमेशा अड़ंगा लगाया है।

लखनऊ के हजरतगंज चैराहे पर लगी डॉ. अम्बेडकर की मूर्ति पर दलित छात्रों द्वारा आयोजित पुलवामा आतंकी हमले में मारे गए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला। इन छात्रों का कार्यक्रम घटना में गम्भीर क्षति को देखते हुए सौम्य था तथा छात्रों ने कोई नारे न लगाने का निर्णय लिया था। वहीं बगल में लगी महात्मा गांधी की मूर्ति पर तमाम किस्म के राष्ट्रवादी संगठन, जिनमें शामिल होने वालों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, इसी मकसद से इकट्ठा हुए थे। पाकिस्तान के खिलाफ इनकी नारेबाजी आवेशपूर्ण व आक्रामक थी, जिसे देखकर शायद गांधीजी भी असहज महसूस करते।

ऐसे में सवाल यह है कि ऐसे आतंकवादी हमले अभी भी जारी क्यों हैं, जबकि देश के प्रधानमंत्री बता चुके हैं कि 2016 में उरी आतंकवादी हमले का सबक सिखाने वाला जवाब पाकिस्तान को निर्णायक सर्जिकल स्ट्राइक में दिया जा चुका है। हिन्दुत्ववादियों का शोर है कि सरकार पाकिस्तान पर और करारा सर्जिकल स्ट्राइक करे, किंतु जब पाकिस्तान को एक सर्जिकल स्ट्राइक से हम निरूत्साहित नहीं कर पा रहे हैं तो क्या जरूरी है कि दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक कामयाब रहेगी ? और हमें यह कैसे पता लगेगा कि सर्जिकल स्ट्राइक कितनी करारी है कि युद्ध ही छिड़ जाए ? युद्ध छिड़ने की स्थिति में यह कैसे पता चलेगा कि उसकी तीव्रता परमाणु अस्त्रों के इस्तेमाल की हद तक पहुंच गई है ? कुल मिलाकर युद्ध तो अनिश्चितताओं से भरा खेल है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ बातचीत न करने का कठोर निर्णय लेकर स्थिति को और बिगड़ने का मौका दिया है। उधर, अमरीका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना को निकालने का निर्णय लिया है जिससे भारत के लिए संकट खड़ा हो गया है।

अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, जो अभी तक आतंकवादी संगठनों को संरक्षण देने के लिए पाकिस्तान सरकार की आलोचना कर रहे थे, को अब समझ आ गया है कि तालिबान से अमरीका की वार्ता कराने में पाकिस्तान की ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अब वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह कहकर मजाक उड़ाते हैं कि मोदी ने काबुल में एक पुस्तकालय, जो असल में भारत की पूर्व सरकार से मिला अफगानिस्तान का संसद भवन है, बनवाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मौका नहीं छोड़ा होगा जहां उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद को संरक्षण देने के लिए अलग-थलग करवाने की कोशिश न की हो, किंतु वे किसी एक भी महत्वपूर्ण देश को अपनी बात मनवा नहीं पाए। जैश-ए-मोहम्मद का मसूद अजहर, जिसका 2001 के संसद भवन पर हमले से लेकर हाल के पुलवामा हमले तक में हाथ है, को संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करवाने के प्रयास में चीन ने हमेशा अड़ंगा लगाया है। रूस जो अभी तक भारत का अभिन्न मित्र माना जाता था, भारत के अमरीका के करीब जाने की कोशिशों को देखते हुए अब पाकिस्तान के साथ संयुक्त सैनिक अभ्यास करने लगा है।

भारत को यह समझना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बार-बार खुद को पीड़ित दिखाकर पाकिस्तान को अलग-थलग करने की कोशिश कामयाब नहीं हो रही है, बल्कि भारत ही अकेला पड़ता जा रहा है। भारत पाकिस्तान के साथ खुलकर युद्ध भी नहीं कर सकता क्योंकि ऐसे किसी भी युद्ध में परमाणु अस्त्रों के इस्तेमाल का खतरा रहेगा। अतः अब भारत के हित में यही है कि वह पाकिस्तान से मित्रता कर व कश्मीर में हालात को सामान्य बना कर इस इलाके में शांति स्थापित करे। अपने आपको और अपनी ही विचारधारा को सही मानना और दूसरे लोगों को गलत मानने की सोच ने ही कश्मीर में जन-जीवन को तबाह कर दिया है।

जब भारत सरकार तालिबान के साथ बातचीत करने को राजी है तो उसे पाकिस्तान सरकार व कश्मीर की राजनीति में दखल रखने वाले समूहों से बातचीत न करने की भूमिका पर पुनर्विचार करना चाहिए। इमरान खान ने करतारपुर गलियार खोलने की पहल कर भारत सरकार को इस परियोजना पर पाकिस्तान के साथ सहयोग करने पर मजबूर कर दिया है क्योंकि भारत सरकार सिक्ख धर्म के अनुयायियों को नाराज करने का खतरा नहीं उठा सकती। भारत को उच्चतम स्तर पर बातचीत की प्रकिया को बहाल करना चाहिए। यह बड़े दुख की बात है कि नवजोत सिंह सिद्धू, जो भारत का एकमात्र ऐसा राजनीतिज्ञ है जो पाकिस्तान से शांति वार्ता की वकालत कर राष्ट्रवाद की राजनीति के विषाक्त माहौल में कुछ समझदारी की बात कर रहा है, की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। जबकि भारत सरकार को तो पाकिस्तान के साथ वार्ता हेतु नवजोत सिंह सिद्धू से इमरान खान की निजी मित्रता का लाभ उठाना चाहिए।

जम्मू व कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए राज्य के विधानसभा चुनाव, हो सके तो लोकसभा के चुनाव के साथ ही करा देने चाहिए और वहां एक चुनी हुई सरकार को सत्ता सौंप देनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण काम जो उसे करना चाहिए वह है, सेना को कश्मीर के अंदरूनी इलाकों से हटाने का। चुनी हुई सरकार पर भरोसा कर जम्मू व कश्मीर की सरकार को दूसरे राज्यों की तरह वहां की पुलिस की मदद से कानून व व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए। सेना की भूमिका सिर्फ सीमा की सुरक्षा तक होनी चाहिए। %सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियमट को धीरे-धीरे जम्मू व कश्मीर से हटा लिया जाना चाहिए, जिसकी मांग उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री रहते हुए भी उठाई थी।

कश्मीर में स्थिति को सामान्य करने के लिए भारत को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी और हालात सामान्य करने के लिए अपने संविधान पर भरोसा करना होगा।

कार्डों से परे रिश्ता

मेरे पिता अपने काम में व्यस्त रहते थे या फिर समाज सेवा में। उनके पास, हमारे या मां के लिए समय नहीं रहता था। इसलिए मां को जहां भी जाना होता था, वे हमारे साथ ही जाती थीं। यह रवैया हमारी शादी के बाद भी चला। मेरी पत्नी शुभा ने भी इसे सहर्ष स्वीकार किया। मां दूसरों के मन की बात समझती थीं और उसे पूरा करने का भरसक प्रयत्न करती थीं। 1980 के दशक में उन्हें दिल की बीमारी हो गयी। मेरी सास ने कई साल अमेरिकी विश्वविद्यालयों में पढ़ाया। मेरी शादी के बाद जब वे पढ़ाने के लिए गयीं तो शुभा, मेरी मां की बीमारी के कारण उन्हें दिल्ली तक छोड़ने नहीं जा पा रही थी। मैंने दिल्ली जाने का प्रोग्राम बना लिया। शाम को उसने फोन किया कि अम्मा की तबीयत खराब है और मैं घर आ जाऊं। उसने डाक्टर को भी बुला लिया था। जब तक मैं घर पहुंचा, डाक्टर मां को देख चुके थे। उन्हें छोड़ने गया तो उन्होंने बताया कि, 'अम्मा की तबीयत ठीक है और तुम दिल्ली जा सकते हो।'

उत्तर पश्चिम रेलवे

खुली ई-निविदा सूचना
(सर्वे एवं निर्माण)

संख्याःएआईआई/एससी/आरओबी/एलसी-18/एनएसडी/टी-1

भारत संघ के राष्ट्रपति एवं उनकी ओर से उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण)-द्वितीय, उत्तर पश्चिम रेलवे, माल रोड, अजमेर निम्नलिखित कार्य हेतु निर्धारित इलैक्ट्रानिक प्रपत्र पर **ऑन लाईन खुली ई निविदा सिस्टम (दो पैकेट)** आमंत्रित करते हैं। **1. कार्य का नाम एवं स्थान** : अजमेर मंडल के अजमेर/चित्तौड़गढ़ सैक्शन में नसीराबाद के कि.मी.23/2-3 पर स्थित समपार फाटक संख्या 18 की एवज में रेलवे स्पान में बो-स्ट्रिंग गर्डर के साथ दो लेन आरओबी के साथ आरयूबी का निर्माण। **2. कार्य की अनुमानित लागतः** रुपये 29.64 लाख। **3. जमा की जाने वाली बयाना राशि** : रुपये 16,32,100/-. **4. ई-निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने तथा खुलने का समय व दिनांक** : 19.03.2019 को 15:00 बजे तक एवं खुलने का समय 15.30 बजे। **5. वेबसाईट विवरण एवं नोटिस बोर्ड का स्थान जहां से निविदा का विस्तृत विवरण देखा जा सकता है:** IREPS website www.ireps.gov.in **6.** कार्यालय का ई-मेल पता : dyce2aii@gmail.com

170-AD/19

हमें / NWRailways पर फॉलो करें

पश्चिम रेलवे - भावनगर मण्डल

रनींग रुम का अपग्रेडेशन एवं एयर कंडीशनींग
ई-निविदा आमंत्रण सूचना

सं. डीआरएम/ईएल/ईटी/बीबीपी/2018-19/22 दि. 20.02.2019, भारत के राष्ट्रपति के पक्ष से मंडल रेल प्रबंधक (ईले.) पश्चिम रेलवे, भावनगर परा की ओर से निम्न कार्य के लिए ई-निविदा आमंत्रित की जाती है, **निविदा सं. 20/2018-19 (R) : कार्य का नामः** भावनगर मंडलः महुवा में अंब्रेला कार्य के अधिन रनींग रुम का अपग्रेडेशन एवं एयर कंडीशनींग, **अनुबंध का मूल्यः** रू 1741326/-, **निविदा शुल्कः** रू 2000/-, **ईएमडीः** रू 34800/-, **पताः** डीआरएम, (इएल) बीबीपी, डीआरएम कार्यालय, भावनगर परा, 364003. निविदाकर्ताओं को अपनी निविदा ऑन लाईन लिंक www.ireps.gov.in के द्वारा लागू की जानी है। अधिक जानकारी के लिए वेबसाईट www.ireps.gov.in पर जाएं। ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि दिनांक 20.03.2019 को समय 15.00 बजे तक है.

89

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

संपादक-चुनीलाल एस. भट्ट, मुद्रक एवं प्रकाशक-मयुर सी. भट्ट, प्रकाशन स्थल-201, 202, 208 नंदन कोम्पलेक्ष, मीठाखली, अहमदाबाद-6. मालिक-कल्याणी पब्लिकेशन प्रा.लि. द्वारा महादेव ऑफसेट, एच-47, रवि एस्टेट, रूस्तम मिल कम्पाउंड, दूधेश्वर, अहमदाबाद में छपवाकर प्रकाशित किया।
फोन-26568477, 26409779.
E : alpaviram1@yahoo.com

करीना कपूर खान 'स्वरस्थप इम्युंनाइज्ड इंडिया' कैम्पेन की एम्बे सेडर बनीं

अहमदाबाद, जानी-मानी अभिनेत्री करीना कपूर खान को स्व स्यू एक इम्युानाइज्ड इंडिया कैम्पेकन का एम्बे सडर घोषित किया गया है। यह देशभर में चलने वाला वैक्सी नेशन और इम्युनाइजेशन कैम्पेकन है। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीयन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने नेटवर्क 18 के साथ मिलकर इस कैम्पेरन को शुरू किया है जिसका लक्ष्यम एक मजबूत नेटवर्क तैयार करना है जोकि बचपन में टीके लगवाने को लेकर जागरूकता फैला सके। इससे एक स्व स्थष भारत का निर्माण हो पायेगा।

इस कैम्पोन के बारे में अपनी बात रखते हुए, करीना कपूर खान ने कहा, ''स्वकस्थक इम्युानाइज्ड इंडिया टीकाकरण और बच्चों को स्वास्थए जीवन देने के महत्व को प्रचारित करने और परिवारों को उसके बारे में जानकारी की एक बेहतरीन पहल है। एक मां होने के नाते यह पहल मेरे दिल के बेहद करीब है, मैं अपने बच्चे को खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिये टीकाकरण के महत्व को समझती हूं। अभाव और खर्च ना उठा पाने की वजह से हमारे देश में अभी भी बड़ी संख्या में नवजात बच्चों की मौतें देखी जाती हैं। अब समय आ गया है एकजुट होने और बदलाव लाने की जिम्मेदारी उठाने का। मैं आदर और नताशा पूनावाला के सीरम इंस्टीजट्यूट और नेटवर्क 18 के इस सफर का हिस्स् बनने के लिये बेहद उत्सारहित हूं और साथ ही मुझे गर्व महसूस हो रहा है। मैं उम्मीरद करती हूं कि इस कैम्पे न के माध्य म से हम हर पेरेंट को एक स्वतस्थ भारत बनाने को लेकर जागरूक और प्रेरित कर पायेंगे।'' (19-8)

श्रीराम जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ 'सीईओ ऑफद ईयर' से सम्मानित

मुंबई: श्रीराम जनरल इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और सीईओ श्री अनिलकुमार अग्रवाल को इंडिया इंश्योरेंस समिट एंड अवार्ड्स-2019 में सीईओ ऑफद ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है।

इंडिया इंश्योरेंस समिट भारत में संपूर्ण बीमा उद्योग और इससे जुड़े ईको सिस्टम के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक व्यापार शिखर सम्मेलन है। बीमा उद्योग में प्रतिष्ठित इंश्योरेंस ईंडिया अवाड्र्स समारोह को लेकर सबसे अधिक उत्सुकता रहती है, जहां हर साल सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को सम्मानित और पुरस्कृत करने के साथ उन्हें मान्यता दी जाती है।

श्रीराम जनरल इंश्योरेंस जयपुर में मुख्यालय वाला एकमात्र गैर जीवन बीमाकर्ता है और गैर-जीवन बीमा क्षेत्र में सबसे अधिक लाभदायक और सफल निजी कंपनियों में से एक है। दस साल के अनुभव के साथ श्रीराम जनरल इंश्योरेंस (एसजीआई) अब 'सी' और 'डी' श्रेणी के शहरों में अपने पदचिह्नों का विस्तार करने के लिए रणनीतिक कदम उठा रहा है, जिसमें अगले 12 महीनों में 50 नई शाखाएं खोलने की योजना भी है।

श्रीराम जनरल इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और सीईओ श्री अनिलकुमार अग्रवाल कहते हैं, 'इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को हासिल करते हुए मैं बेहद खुश और आभारी हूं। हमारी योजना 'सी' और 'डी' शहरों में अपनी उपस्थिति बढ़ाकर अपने वर्तमान शाखा नेटवर्क को 210 शाखाओं तक विस्तारित करने की है। इस तरह हम प्रौद्योगिकी और नवाचारों का लाभ उठाते हुए 'आम आदमी' की सेवा के हमारे व्यापार दर्शन को और आगे बढाने में कामयाब हो पाएंगे।'' (1)

एफएजीएमआईएल ने 605 करोड़ रुपये की सफेद सीमेंट संयंत्र परियोजना स्थापित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

नई दिल्ली। अपने विविधता कार्यक्रम के अंतर्गत एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड (एफएजीएमआईएल) ने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में नोहराधार गांव के नजदीक सफेद सीमेंट का एक संयंत्र स्थापित करने के लिए एक परियोजना शुरू की है। परियोजना पर 605 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। यह देश का चौथा सफेद सीमेंट संयंत्र होगा। संयंत्र की संस्थापित क्षमता 0.3 मिलियन टन प्रतिवर्ष होगी और इससे करीब 150 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इस संयंत्र के वर्ष 2022 तक चालू हो जाने की उम्मीद है। यह सिरमौर जिले के विकास में मील का पत्थर शामिल होगा। परियोजना को एक निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए एफएजीएमआईएल की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्रीमती अल्का तिवारी हिमाचल प्रदेश के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की उपस्थिति में आज शिमला में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

एफएजीएमआईएल भारत सरकार का उपक्रम है जिसका प्रशासनिक नियंत्रण रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग के पास है। यह राजस्थान में खनिज जिप्सम के खनन और विपणन में लगा हुआ है। एफएजीएमआईएल मिनीरत्न-द्वद्ध कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय जोधपुर (राजस्थान) में है। इसकी राजस्थान में 15 परिचालित जिप्सम खाने है। इसने 01-04-2003 में काम करना शुरू किया था और पिछले 15 वर्षों के दौरान अपना दायरा बढ़ाकर 3248त्न कर लिया है।

प्रधानमंत्री कल इस्कॉन, नई दिल्ली में गीता आराधना महोत्सव में सम्मिलित होंगे

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल नई दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन-ग्लोरी ऑफ इंडिया कल्चरल सेंटर में गीता आराधना महोत्सव में सम्मिलित होंगे। वे आयोजन में विश्व भर के इस्कॉन श्रद्धालुओं द्वारा तैयार की हुई भग्वदगीता का अनावरण करेंगे। यह भग्वदगीता विश्व में अपनी तरह की अनोखी है और इसका आकार 2.8 मीटर और भार 800 किलोग्राम से अधिक है। इसमें टीका सहित भग्वदगीता के मूल श्लोक मौजूद हैं। प्रधानमंत्री भग्वदगीता के पृष्ठों को खोलकर उसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे।

राष्ट्रपति ने कानपुर में डीएवी कॉलेज के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया और बीएनएसडी कॉलेज के वार्षिक दिवस को संबोधित किया

नई दिल्ली। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने आज कानपुर में डीएवी कॉलेज, कानपुर के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। एक अन्य समारोह में राष्ट्रपति ने बीएनएसडी इंटर कॉलेज तथा शिक्षा निकेतन कानपुर के पुराछात्र सम्मेलन और वार्षिक दिवस को संबोधित किया। राष्ट्रपति युवा अवस्था में इन दोनों संस्थानों में पढ़े थे।

इससे पहले राष्ट्रपति बालाजी मंदिर, कानपुर तथा धम्म कल्याण कानपुर इंटरनेशनल विपासना मेडिटेशन सेंटर गए।

राइजिंग इंडिया समिट के अवसर पर प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ

नई दिल्ली। अभी कुछ देर पहले ही मुझे राष्ट्रीय समर स्मारक को देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। ये भी संयोग देखिए कि इसके ठीक बाद राइजिंग इंडिया समिट में एक ऐसे विषय पर बोलने का अवसर मिल रहा है, जो मेरे हृदय के बहुत करीब है।

मैं नेटवर्क 18 टीम को ये विषय- Beyond Politics: Defining National Priorities तय करने के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, राष्ट्र निर्माण की दिशा क्या हो, एक राष्ट्र के तौर पर हमारी प्राथमिकता क्या हो, इस पर निरंतर मंथन बहुत आवश्यक है।

अब जब मैं मीडिया के साथियों के बीच हूं तो इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आपका पसंदीदा तरीका ही अपनाउंगा। यानि पहले क्या था और अब क्या है। इसी से आपको भी साफ हो जाएगा कि पहले क्या प्राथमिकता थी, और अब क्या है। इसी से ये भी पता चलेगा कि राजनीति से अलग हटकर जब राष्ट्रनीति को प्राथमिकता दी जाती है, तो किस तरह के परिणाम निकलते हैं।

साथियों, वर्ष 2014 के पहले देश में स्थिति ये थी कि जो बढ़ना चाहिए था वो घट रहा था और जो घटना चाहिए था, वो बढ़ रहा था।

अब जैसे, महंगाई का ही उदाहरण लीजिए। हम सबको पता है कि महंगाई दर नियंत्रण में रहनी चाहिए। लेकिन असलियत क्या थी? पिछली सरकार में जरूरी वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे थे। महंगाई सुरसा की तरह मुंह खोल रही थी।

आप सभी को, विशेषकर न्यूजरूम के प्रोड्यूसर्स को याद होगा कि महंगाई डायन खाए जात है, आपको कितनी बार अपने शोज़ में चलाना पड़ा था।

साथियों, आप ने तब खूब रिपोर्ट किया था कि महंगाई दर 10 प्रतिशत का आंकड़ा भी पार कर गई थी। लेकिन आज हमारी सरकार में महंगाई दर गिरकर 2-4 प्रतिशत के आसपास रह गई है। ये फर्क तब आता है जब राजनीति से हटकर राष्ट्रनीति को प्राथमिकता दी जाती है।

साथियों, यही स्थिति इनकम टैक्स को लेकर थी। मिडिल क्लास छूट के लिए निरंतर आवाज़ देता रहता था लेकिन राहत के नाम पर कुछ नहीं मिलता था। हमारी सरकार ने इनकम टैक्स पर छूट की सीमा पहले ढाई लाख रुपए तक की, फिर 5 लाख तक की आय के लिए टैक्स को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया और इस बार तो 5 लाख तक की टैक्सेबल इनकम को ही टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया है।

साथियों, अब GDP Growth की ही बात करूं तो आप पहले की सरकार और अब की सरकार, पहले की प्राथमिकता और अब की प्राथमिकता का फर्क, और स्पष्टता से समझ पाएंगे। आपको पता होगा कि अटल जी की सरकार ने वर्ष 2004 में यूपीए को 8 प्रतिशत विकास दर वाली अर्थव्यवस्था सौंपी थी। लेकिन वर्ष 2013-14 में जब यूपीए की विदाई हो रही थी, तब विकास दर 5 प्रतिशत के क़रीब पहुंच गई थी।

2014 में एक बार फिर हमने इस चुनौती को स्वीकार किया। आज एक बार फिर GDP Growth Rate को हमारी सरकार ने 7 से 8 प्रतिशत के बीच पहुंचा दिया है। वो बढ़े हुए को घटा के गए और हमने घटे हुए को फिर बढ़ा दिया। ये हमारी प्राथमिकता है।

साथियों, यही हाल भारत की Global Standing का रहा। हम सब पढ़ते आए थे कि इक्कीसवीं सदी भारत की सदी है। लेकिन यूपीए सरकार में क्या हुआ? भारत को 2013 तक आते-आते दुनिया के 'Fragile Five' देशों में पहुंचा दिया गया। आज एक बार फिर सरकार के दृढ़ निश्चय और सवा सौ करोड़ देशवासियों के परिश्रम के बल पर भारत 'Fastest Growing Major Economy' बन गया है। साथियों, Ease of Doing Business की रैंकिंग में भी पिछली सरकार ने जाते जाते देश का नाम डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये कांग्रेसी संस्कृति का ही परिणाम था कि साल 2011 के 132वें नंबर से फिसलकर भारत की रैंकिंग 2014 में 142 तक चली गई। आप सोचिए कि उस समय देश में बिजनेस का कैसा वातावरण बना दिया गया था। इस रैंकिंग में सुधार करके देश को 77वें स्थान पर पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है।

साथियों, पिछली सरकार के दौरान ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में देश की रैंकिंग इसलिए भी फिसल रही थी, क्योंकि भ्रष्टाचार का ग्राफ आसमान छू रहा था। स्पेक्ट्रम से लेकर submarine तक, और Coal से लेकर CWG तक, कुछ भी भ्रष्टाचार से छूटा नहीं था। उस दौर में हर संस्था चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, CAG हो, मीडिया हो, हर जगह सरकारी भ्रष्टाचार की फाइलें खुल रही थीं।

आज स्थिति ये है कि राजनीतिक विरोध के लिए विपक्ष के हमारे साथी छद्म तरीके से कोर्ट जाते हैं और वहां से उनको फटकार लगती है और सरकार को Appreciation मिलता है। सरकारी संस्कारों में ये सार्थक बदलाव बीते हमारी सरकार के दौरान आया है।

भाइयों और बहनों, राजनीति से अलग, हमारी सरकार की प्राथमिकताएं कैसे अलग रहीं, कैसे हम एक योजना से दूसरी को जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उससे सिस्टम कैसे Smooth और Transparent हो रहा है, इसके एक और उदाहरण पर मैं आपसे विस्तार से बात करना चाहता हूं।

आपको याद होगा कि जब हमने चार साल पहले जनधन योजना शुरू की थी, तो कितना मजाक उड़ाया गया था। कुछ लोग कहते थे कि गरीबों का बैंक खाता खुलवाकर हमने कौन सा तीर मार लिया। कई लोगों ने तो यहां तक कहा कि जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, वो बैंक में खाता खुलवाकर क्या करेंगे?

ऐसी ही मानसिकता की वजह से हमारे देश में आजादी के इतने वर्षों बाद भी, आधे से ज्यादा लोगों के पास बैंक खाते नहीं थे। अब आज हमारी सरकार के प्रयासों की वजह से देश में 34 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक खाते खुले हैं।

साथियों, जनधन अकाउंट खुलने के बाद हमने उन्हें आधार नंबरों से जोड़ा, कोशिश की, कि ज्यादा से ज्यादा अकाउंट मोबाइल नंबर से भी जुड़ जाएं। इधर हम देश में जनधन खाते खोल रहे थे, उधर उन सरकारी योजनाओं को भी खंगाला जा रहा था, जिसमें लाभार्थियों को पैसे दिए जाने का प्रावधान था। पहले ये पैसे कैसे मिलते थे, कौन बीच में उन्हें पचा जाता था, ये भी आपको पता है।

भाइयों और बहनों, हम एक-एक करके योजनाएं खंगालते गए और उन्हें जनधन खातों से जोड़ते गए। आज स्थिति ये है कि सरकार की सवा चार सौ से ज्यादा योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर हो रहा है।

हमारी सरकार के दौरान करीब-करीब 6 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजे हैं। और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि पहले की तरह 100 में से सिर्फ 15 पैसे नहीं, बल्कि पूरे पैसे लाभार्थियों को मिल रहे हैं।

सरकार के इन प्रभावों का भ्रष्टाचार और कालेधन पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये भी आपको जानना जरूरी है।

साथियों, जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल को जोड़ने का नतीजा ये हुआ कि एक के बाद एक करके कागजों में दबे हुए फर्जी नाम सामने आने लगे। आप सोचिए, अगर आपके ग्रुप में या चैनल में 50 लोग ऐसे हो जाएं जिनकी हर महीने सैलरी जा रही हो, लेकिन वो हकीकत में हो ही नहीं, तो क्या होगा।

अब यहां ।क्रवाले लोग कहेंगे कि हमारे यहां ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन साथियों, पहले की सरकारों ने, देश में जो व्यवस्था बना रखी थी, उसमें एक-दो नहीं 8 करोड़ ऐसे फर्जी नाम थे, जिनके नाम पर सरकारी लाभ ट्रांसफर किया जा रहा था।

साथियों, सरकार के इस प्रयास से एक लाख 10 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा गलत हाथों में जाने से बच रहे हैं। और जब मैं ये कहता हूं कि 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपए बच रहे हैं, तो ये भी सोचिए कि पहले यही पैसे किसी और के पास जा भी तो रहे थे।

अहमदाबाद - भगत की कोठी साप्ताहिक एक्सप्रेस दूंदारा स्टेशन पर रूकेगी

अहमदाबाद, माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल की पहल पर रेल मंत्रालय द्वारा ट्रेन संख्या 14803/14804 भगत की कोठी-अहमदाबाद (साप्ताहिक) एक्सप्रेस को दि.01 मार्च 2019 से उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के दूंदारा स्टेशन पर प्रायोगिक तौर पर आगामी छह माह के लिए स्टोपेज प्रदान किया जा रहा है. तदनुसार ट्रेन संख्या 14803 भगत की कोठी-अहमदाबाद साप्ताहिक एक्सप्रेस दि.01 मार्च 2019 से प्रात-10.59 बजे दूंदारा पहुंचकर 11.00 बजे प्रस्थान करेगी. वापसी में ट्रेन संख्या 14804 अहमदाबाद-भगत की कोठी साप्ताहिक एक्सप्रेस दिनांक 02 मार्च 2019 से प्रात-05.32 बजे दूंदारा स्टेशन पर पहुंचकर 05.33 बजे प्रस्थान करेगी.

स्थानीय निवासियों की मांग पर रेल मंत्रालय द्वारा उपरोक्त ठहराव 01 मार्च 2019 से आगामी छह माह के लिए प्रदान किये जा रहे हैं.

पश्चिम रेलवे की चर्चगेट स्थित ऐतिहासिक प्रधान

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक ए. के. गुप्ता तथा महाराष्ट्र सर्किल के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल एच. सी. अग्रवाल सोमवार, 25 फरवरी, 2019 को मुंबई के चर्चगेट स्थित प्रधान कार्यालय भवन में विशेष आवरण के विमोचन एवं अनावरण कार्यक्रम में दिखाई दे रहे हैं।

अहमदाबाद, विरासती माह के दौरान रेलवे की समृद्धशाली धरोहर का जश्न मनाने के क्रम में पश्चिम रेलवे ने सुनहरी पुरानी स्मृतियों एवं गौरवशाली इतिहास के स्मरण को ताज़ा करने के उद्देश्य से कई गतिविधियों की योजना तैयार की है। पुरानी स्मृतियों को सहेजने की इस अनूठी पहल को आगे बढ़ाते हुए पश्चिम रेलवे द्वारा चर्चगेट स्थित अपने प्रधान कार्यालय भवन की समृद्ध विरासत को समर्पित एक विशेष आवरण तैयार किया गया। इस विशेष आवरण का विमोचन सोमवार, 25 फरवरी, 2019 को मुंबई के चर्चगेट स्थित पश्चिम रेलवे प्रधान कार्यालय भवन में महाराष्ट्र सर्किल के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल एच. सी. अग्रवाल द्वारा किया गया, जिन्होंने इसके पहले एलबम को पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक ए. के. गुप्ता को भेंट किया।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी रविंद्र भाकर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पश्चिम रेलवे का प्रधान कार्यालय भवन एक ग्रेड-द्ध हैरिटेज संरचना है। इस इमारत का निर्माण कार्य 1894 में प्रारम्भ किया गया था एवं वर्ष 1899 में 7.5 लाख रु. की लागत से इसे पूर्ण किया गया। पहले यह इमारत पूर्ववर्ती बॉम्बे बरोडा एवं सेंट्रल इंडिया रेलवे (BB & CI) का मुख्यालय हुआ करती थी तथा अब यह पश्चिम रेलवे को प्रधान कार्यालय भवन के रूप में अपनी सेवाएँ प्रदान कर रही है। यह भव्य इमारत प्रख्यात विक्टोरिया गोथिक, इटालियन तथा इंडो-सारसेनिक वास्तु शैली के मिश्रण से निर्मित की गई है। विशेष आवरण के विमोचन के अवसर पर पश्चिम रेलवे के विभिन्न प्रधान विभागाध्यक्ष तथा भारतीय डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के प्रारम्भ में पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी रविंद्र भाकर ने सभी अतिथियों को स्वागत किया तथा चर्चगेट स्थित पश्चिम रेलवे प्रधान कार्यालय की विरासती भवन के गौरवशाली इतिहास के बारे में सभी को अवगत कराया।

भोपाल और जोरहाट में एनआईटी का उद्घाटन

नई दिल्ली। केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने 22 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश के भोपाल और असम के जोरहाट में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) का उद्घाटन किया। दोनों संस्थान वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान हैं ।

सरकार के कई क्षेत्रों, नीतियों, और मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स जैसी योजनाओं में डिजाइन और नवोन्मेष को प्रमुख महत्व मिलने के साथ ही डिजाइन शिक्षा को बढ़ावा देना आवश्यक हो गया है। राष्ट्रीय डिजाइन नीति 2007 में डिजाइन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए एनआईडी अहमदाबाद की तर्ज पर देश के अन्य भागों में भी डिजाइन संस्थानों की स्थापना किये जाने की सिफारिश की गई थी। 434 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ चार नए एनआईडी आंध्र प्रदेश (अमरावती), असम (जोरहाट), मध्य प्रदेश (भोपाल) और हरियाणा (कुरुक्षेत्र) में स्थापित किए गए हैं।

देश के विभिन्न क्षेत्रों में नए एनआईडी स्थापित करने से डिजाइन में अत्यधिक कुशल मानवशक्ति तैयार करने में मदद मिलेगी, जो शिल्प, हथकरघा, ग्रामीण प्रौद्योगिकी, लघु, मध्यम और बड़े उद्यमों के लिए टिकाऊ डिजाइन हस्तक्षेप तथा क्षमता, क्षमता और संस्थान निर्माण के लिए आउटरीच कार्यक्रम प्रदान करके प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरह से रोजगार के अवसरों का सृजन करेंगे।

सुरेश प्रभु ने उद्घाटन सत्र में कहा कि देश के लिए वैश्विक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनना महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से डिजाइन की अवस्था में, जहां अधिकतम मूल्य वृद्धि होती है। उन्होंने कहा कि नए एनआईडी देश में डिजाइनरों की आवश्यकता को पूरा करेंगे और उन्हें रोजगार के अवसरों से रूबरू कराएंगे, जो देश को उच्च सामाजिक-आर्थिक विकास की ओर ले जाएगा।

उन्होंने कहा कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के प्रथम डिजाइन संस्थान के रूप में असम के जोरहाट में एनआईडी की स्थापना से पूर्वोत्तर की युवा रचनात्मक प्रतिभाओं और डिजाइन के क्षेत्र में दिलचस्पी रखने वालों को महत्वपूर्ण अवसर मिलेंगे।

एनआईडी भोपाल जुलाई, 2019 से औद्योगिक डिजानइ, संचार डिजाइन और सिलेसिलाए कपड़े एवं वस्त्र डिजाइन विषय में चार साल के अंडर ग्रेज्युवेट पाठयक्रमों में 60 छात्रों के साथ अपनी अकादमिक यात्रा की शुरूआत करेगा। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए जनवरी 2019 में लिखित परीक्षा हुई थी।

यह परिसर 30 एकड़ में फैला है और बेहतरीन सुविधाओं और प्रौद्योगिकी से संपन्न है। यहां उपलब्ध कुछ अत्याधुनिक सुविधाओं में डिजाइन स्टूडियो, कार्यशालाएं, आईटी सेंटर, पुस्तकालय, संसाधन केन्द्र, ऑडिटोरियम, एम्फीथिएटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, व्यायामशाला और छात्रावास शामिल हैं। यह संस्थान देश में डिजाइन आधारित शिक्षा में सुधार लाने तथा उद्योग में डिजाइन अनुसंधान आधारित नवाचार दृष्टिकोण शुरू करने का इच्छुक है।

एनआईडी जोरहाट डिजिटल और स्वदेशी प्रौद्योगिकियों दोनों में सामाजिक, स्वास्थ्य, आजीविका तथा जीवन शैली के क्षेत्रों में रचनात्मक और नवोन्मेष पर ध्यान केन्द्रित करते हुए डिजाइन शिक्षा की परिकल्पना करता है। 30 एकड़ क्षेत्र में फैला यह परिसर स्टूडियो, आईटी लैब वर्कशॉप्स, पुस्तकालय, 200 से ज्यादा छात्रों की क्षमता वाले छात्रावासों से संपन्न होगा।

सरकार के कई क्षेत्रों, नीतियों, और मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स जैसी योजनाओं में डिजाइन और नवोन्मेष को प्रमुख महत्व मिलने के साथ ही डिजाइन शिक्षा को बढ़ावा देना आवश्यक हो गया है। राष्ट्रीय डिजाइन नीति 2007 में डिजाइन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए एनआईडी अहमदाबाद की तर्ज पर देश के अन्य भागों में भी डिजाइन संस्थानों की स्थापना किये जाने की सिफारिश की गई थी। 434 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ चार नए एनआईडी आंध्र प्रदेश (अमरावती), असम (जोरहाट), मध्य प्रदेश (भोपाल) और हरियाणा (कुरुक्षेत्र) में स्थापित किए गए हैं।

देश के विभिन्न क्षेत्रों में नए एनआईडी स्थापित करने से डिजाइन में अत्यधिक कुशल मानवशक्ति तैयार करने में मदद मिलेगी, जो शिल्प, हथकरघा, ग्रामीण प्रौद्योगिकी, लघु, मध्यम और बड़े उद्यमों के लिए टिकाऊ डिजाइन हस्तक्षेप तथा क्षमता, क्षमता और संस्थान निर्माण के लिए आउटरीच कार्यक्रम प्रदान करके प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरह से रोजगार के अवसरों का सृजन करेंगे।

सुरेश प्रभु ने उद्घाटन सत्र में कहा कि देश के लिए वैश्विक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनना महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से डिजाइन की अवस्था में, जहां अधिकतम मूल्य वृद्धि होती है। उन्होंने कहा कि नए एनआईडी देश में डिजाइनरों की आवश्यकता को पूरा करेंगे और उन्हें रोजगार के अवसरों से रूबरू कराएंगे, जो देश को उच्च सामाजिक-आर्थिक विकास की ओर ले जाएगा।

प्रधानमंत्री ने भूतपूर्व सैनिकों को संबोधित किया, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित करने के लिए अखंड ज्योति प्रज्जवलित की। प्रधानमंत्री ने स्मारक के विभिन्न खंडों का दौरा किया।

इससे पहले भूतपूर्व सैनिकों की विशाल रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह लाखों सैनिकों के पराक्रम और समर्पण का परिणाम है कि भारतीय सेना को आज दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक माना जाता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि दुश्मनों के खिलाफ और प्राकृतिक आपदाओं से मुकाबला करने के लिए हमारे जांबाज सैनिक अग्रिम रक्षा पंक्ति में रहते हैं।

प्रधानमंत्री ने पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों की शहादत को याद किया। उन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहूति देने वाले सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि आज विश्वभर में नए भारत का कद बड़ा है और यह उसकी सशस्त्र सेना में बड़े उपायों के कारण संभव हुआ है। उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक अथवा राष्ट्रीय समर स्मारक को समर्पित करने पर खुशी जाहिर की।

प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि केन्द्र सरकार ने सैनिकों और पूर्व सैनिकों को 'वन रैंक, वन पेंशन' उपलब्ध कराने का अपना संकल्प पूरा किया है। उन्होंने कहा कि ओआरओपी के परिणास्वरूप पेंशन में 40 प्रतिशत तक का इजाफा हुआ और 2014 की तुलना में सैन्य कर्मियों के वेतन में 55 प्रतिशत तक का इजाफा हुआ है।

प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल की मांग होती रही है। इस संदर्भ में उन्होंने घोषणा की कि तीन सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल बनाए जाएंगे।

सशस्त्र बलों के प्रति सरकार की अन्य पहलों का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना दिवस, नौसेना दिवस और वायुसेना दिवस के अवसरों पर सैन्य कर्मियों के अभिनव प्रयोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने 15 अगस्त, 2017 को लॉन्च किए जाने वाले वीरता पुरस्कार पोर्टल का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अब फाइटर पायलट बनने के अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में महिला अधिकारियों को अपने पुरुष समकक्षों के बराबर स्थायी कमीशन के लिए अवसर मिल रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा खरीद की समूची ईको-प्रणाली में बदलाव की शुरूआत कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार का दृष्टिकोण पारदर्शी और बराबर का अवसर प्रदान करना रहा है। उन्होंने 'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहन दिए जाने के विषय पर बल दिया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना ने संयुक्त राष्ट्र के 70 प्रमुख शांति मिशनों में से लगभग 50 मिशनों में भागीदारी की है। लगभग 2 लाख सैनिक इन कार्रवाइयों का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय नौ सेना द्वारा 2016 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जहाजी बेड़ा समीक्षा में 50 देशों की नौ सेना ने भाग लिया।

गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया ने जीता अपने किसान सामुदायिक कार्यक्रम के लिए 6ठा वार्षिक ग्रीनटेक सीएसआर गोल्ड अवार्ड 2018

गुंटूर, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया ने अपने किसान सामुदायिक कार्यक्रम के लिए 6ठा वार्षिक ग्रीनटेक सीएसआर गोल्ड अवार्ड 2018 जीता। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया को आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में बर्ली तम्बाकू किसान समुदाय कार्यक्रम के लिए 6ठे वार्षिक ग्रीनटेक सीएसआर अवार्ड 2018 का स्वर्ण पुरस्कार विजेता घोषित किया गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार सुश्री वैशाली डे, प्रमुख, सीएसआर, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया, ने पणजी, गोवा में प्राप्त किया।

यह पुरस्कार आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के सीमांत, गरीब किसानों के जीवन को बदलने वाली कंपनी की सीएसआर पहलों के प्रभाव को मान्यीता देता है। 1 से 5 एकड़ के बीच भूमि जोत वाले बर्ली के सीमांत तंबाकू किसान सूखे और सिंचाई के लिए पानी की कमी से जूझते रहते हैं जिसमें वे केवल एक ही फसल उगा पाते हैं। इसी संदर्भ में, किसान मौसमी रोजगार, कम आय, सौदेबाजी की कम शक्ति, बढ़ते कर्ज और श्रम मूल्यों में कमी के जाल में फंस जाते हैं। इन मुद्दों के अलावा, सूखे से उत्पन्न बड़े सामुदायिक मुद्दे हैं जैसे सुरक्षित और पेयजल की कम सुलभता, भूजल में उच्च फ्लोराइड संदूषण, शौचालयों की कम सुलभता, सामुदायिक स्वच्छता और सफाई का अभाव, खेती के अलावा शिक्षा और कौशल की सीमित सुलभता, और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध न होने के कारण, किसानों और मजदूरों के बच्चे अनजाने में बाल श्रम में धकेल दिए जाते हैं। -